भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1202

(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, 2026/21 माघ,1947 (शक) को दिया जाना है)

उपभोग मंदी और मांग में कमी

1202. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री दिग्विजय सिंह:

श्री हारिस बीरान:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफई) की वर्ष-वार वृद्धि दर क्या है;

(ख) इसी अवधि के लिए कुल पीएफई में ग्रामीण और शहरी उपभोग का हिस्सा कितना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए ग्रामीण और शहरी उधारकर्ताओं के अनुसार अलग-अलग उपभोग ऋणों की वर्षवार वृद्धि दर क्या है; और

(घ) 31 दिसम्बर, 2025 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोग ऋण का कुल बकाया मूल्य कितना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) अनुमान समग्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय स्तर पर पीएफसीई (स्थिर मूल्य, 2011-12) में वर्षवार वृद्धि नीचे दी गई है:

वित्त वर्ष	**निजी अंतिम उपभोग व्यय वृद्धि (स्थिर मूल्य, 2011-12) (प्रतिशत)**
2022-23	7.5
2023-24	5.6
2024-25 (पीई)	7.2
2025-26 (एफएई)	7.0

नोट: पीई का अर्थ अनंतिम वास्तविक है, एफएई का अर्थ प्रथम अग्रिम अनुमान है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीएफसीई का ग्रामीण-शहरी ब्रेकडाउन आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया जाता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा व्यक्तिगत ऋणों (आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, वाहनों, शिक्षा, व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड और अन्य के लिए ऋणों सहित) के लिए बकाया ऋण की वर्ष-वार वृद्धि दर नीचे दी गई है।

	बकाया ऋण वाले खातों की संख्या में वृद्धि (प्रतिशत)		
	31 मार्च, 2025	**31 मार्च, 2024**	**31 मार्च, 2023**
ग्रामीण	20.2	11.1	5.7
अर्ध-शहरी	12.5	18.9	10.8
शहरी	23.6	20.1	6.5
	बकाया राशि में वृद्धि (प्रतिशत)		
	31 मार्च, 2025	**31 मार्च, 2024**	**31 मार्च, 2023**
ग्रामीण	18.1	24.6	17.9
अर्ध-शहरी	12.4	27.2	18.5
शहरी	12.8	29.8	17.2

(घ): आरबीआई के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) द्वारा व्यक्तिगत ऋणों (आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं, वाहनों, शिक्षा, व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड और अन्य के लिए ऋण सहित) का कुल बकाया मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों में ₹4.8 लाख करोड़, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ₹10.5 लाख करोड़ और शहरी क्षेत्रों में ₹15.0 लाख करोड़ रुपये था।

*****